

Shri Alagesan: I have dealt with this question in my answer. I have said that this was gone into by a Special Officer. He was able to come across certain differences in the rates charged which were working to the detriment of Indian exports. When this question was brought before the Conference Lines, they saw the force of the argument on our side and reduced the rates.

Shri T. N. Singh: May I know whether the disparities discovered by the Special Officer are comprehensive enough; do they cover all cases, possible cases, known cases? Or do they refer only to a few cases in which they have been able to persuade the Conference Lines?

Shri Alagesan: In some cases only we were able to persuade them. He was able to get the tariff rates for several commodities that are being carried from Indian ports and ports of other neighbouring countries. It was very difficult to get the tariff rates in the first place. But he was able to obtain some data. And on the basis of that data the questions were taken up later on with the Conference Lines who agreed to fall in line with our wishes.

Development of Calcutta Port

*1126. **Shri Gidwani:** Will the Minister of Transport be pleased to state the projects which will be taken up for the development of Calcutta Port during the Second Five Year Plan and what will be their cost?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan): A Statement is laid on the Table of the Lok Sabha. [See Appendix VII, annexure No. 1]

Shri Gidwani: From the statement I find that out of Rs. 21,58,35,000 provided for cost of works in the Second Five Year Plan, Rs. 8,56,21,000 have been carried over from the cost of works in the First Five Year Plan. May I enquire as to what were the reasons for not taking up all the schemes under the First Five Year Plan and completing them?

Shri Shahnawaz Khan: The first one was that the execution of the projects was taken up after two years of the Plan period had lapsed. Then, certain large projects like the construction of quarters, general cargo berths, and suction dredgers were included at a later date. Equipment like crane, dredgers, launches could not be procured against orders and they had to be manufactured. And lastly, there was the difficulty of obtaining steel in time.

Shri Gidwani: Has the attention of Government been drawn to a statement made by Mr. I. Matsumoto, Managing Director of the Japanese Shipping Company that there were delays in the Indian ports and ships were delayed in some cases by a month resulting in loss to ships and ship-owners?

If so, may I know what steps are being taken immediately to relieve the congestion?

The Deputy Minister of Railway and Transport (Shri Alagesan): Regarding the delays that occur in our ports, this matter was taken up in right earnest and the congestion in our ports has been considerably reduced. We must also remember that a much larger volume is handled by our ports now than what they ever used to do before. Certain steps were taken, like the piece rate system in Bombay. The question is under consideration with regard to the other major ports like Calcutta and Madras; and with the improvement in the working of the ports, the delays have been considerably reduced. The position was so before. But we are taking continuous steps to reduce the delays.

Shri H. N. Mukerjee: In view of Calcutta port having to handle about 4,000 tons of steel every day from 1957 onwards and the prohibitive cost of dredging in the river Hooghly, what steps are being taken particularly because the Ganga Barrage is a doubtful factor in the Second Plan?

Shri Alagesan: I think the hon. Member is trying to club too many things—however desirable they may be by themselves. As far as the clearance of the steel cargo is concerned, it has been answered the other day also in this House. We have created dumps and we have also asked the consignees to take delivery as soon as they are delivered at the quay side. This is the method which has been adopted for clearing the large steel cargo.

पटना में हवाई अड्डा

*११२८. श्री श्रीनारायण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में या उसके निकट प्राधुनिक सुविधाओं से पूर्ण एक बड़ा हवाई अड्डा बनवाने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है कि यह हवाई अड्डा कहाँ बनाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राव) :

(क) से (ग) में सभा पटल पर एक बिबरन-पत्र रखा रहा है जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध सं० ३]

इस विवरण पत्र में एक संशोधन यह है कि "भीटा" के स्थान पर "बिहटा" पढ़ा जाना चाहिये ।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण पत्र से पता चलता है कि पटना में जो विमान क्षेत्र है वह वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति ठीक तरह से करता है । साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि उसके विकास का प्रश्न विचाराधीन है । मैं जानना चाहूंगा कि यह विकास की कल्पना किस तरह से की गई है ?

श्री जगजीवन राम : इसको बहुत अधिक बढ़ाने की गुंजाइश तो है ही नहीं लेकिन फिर भी हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अगर बिहटा से काम लेंगे तो वह बहुत दूर पड़ जाता है । जब तक यहां काम चल सकता है तब तक तो यहां चलायेंगे लेकिन जब ज्यादा बड़े प्लेन चलने लगेंगे तो बिहटा का इस्तेमाल करेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास : बिहटा में एक बड़े पैमाने का विमान क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस के बारे में जांच भी शुरू होने वाली है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पटना के आसपास, बिहटा से नजदीक, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कि बड़े विमानों के उतारने के लिये विमान क्षेत्र बनाया जा सके ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, इसमें खर्च का भी तो ख्याल रखना पड़ता है । बिहटा में तो पहले से विमान क्षेत्र बना हुआ है, उसको हम लेना चाहते हैं ताकि जेट और बड़े विमान वहां पर उतर सकें । लेकिन फिलहाल तो पटना विमान क्षेत्र को ही और बढ़ा कर उसको इस्तेमाल करेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूँ कि पटना के हवाई भ्रष्टे पर डकोटा से बड़ा हवाई जहाज, जैसे वाइकिंग वगैरह, उतर सकता है या नहीं, और अगर नहीं, तो क्या यह प्रश्न भी विचाराधीन है

और क्या डकोटा से बड़े हवाई जहाजों को वहां उतारने के लिये कोई योजनायें बनाई जा रही हैं ?

श्री जगजीवन राम : यही तो कहा है कि पटना के हवाई भ्रष्टे को बढ़ाया जायेगा ताकि वाइकिंग जहाज वहां पर उतारे जा सकें । लेकिन जब वाइकाउंट वगैरह आ जायेंगे तो मुश्किल हो जायेगी । उनके उतारने के लिये वहां पर जगह नहीं है ।

श्री अग्निचंद्र सिंह : क्या यह सही है कि पटना हवाई भ्रष्टे के विस्तार के लिये सरकार के पास पांच बरस से योजना है, लेकिन अन्तिम निर्णय इसलिये नहीं हो सका है कि बिहार सरकार जो जमीन देगी, या जो जमीन अधिभूत करके देगी, उसके लिये वह बाजार दर पर दाम मांगती है, लेकिन कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री देना नहीं चाहती, और इसीलिये बिहटा को बढ़ाना चाहती है जो कि पटना से दूर है और जिसकी वजह से पटना वालों को असुविधा होगी ।

श्री जगजीवन राम : जैसा मैंने आपको बताया, पटना हवाई भ्रष्टा तो है ही और उसको इस्तेमाल करने की हमारी योजना है, लेकिन उसके अधिक विकास की गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, और जब तक उन मकानों को न तोड़ा जाय वह हवाई भ्रष्टा इस योग्य नहीं बनाया जा सकता कि वहां पर वाइकाउंट विमान उतर सकें । पटना हवाई भ्रष्टे के विकास के बारे में बिहार सरकार से बातचीत चल रही है ।

श्री रा० स० तिवारी : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पटना हवाई भ्रष्टे को बढ़ाया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूँ कि और भी हवाई भ्रष्टों की मरम्मत की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : होगी तो सही, लेकिन इस वक्त वह हमारे सामने नहीं हैं ।